

## 19 June 2026: Top Current Affairs News GK (Hindi & English)

1] Union Minister Pralhad Joshi recently launched the Green Hydrogen Certification Portal of India (GHCI Portal) during a national workshop in New Delhi. On which date is this transparent digital platform scheduled to become fully operational?

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान 'ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया' (GHCI Portal) लॉन्च किया है। यह पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस तारीख से पूरी तरह चालू होने वाला है?

- A. June 21, 2026 / 21 जून 2026
- B. July 1, 2026 / 1 जुलाई 2026 (July 1, 2026)
- C. August 15, 2026 / 15 अगस्त 2026
- D. October 2, 2026 / 2 अक्टूबर 2026

✓ **Answer: B. July 1, 2026 / 1 जुलाई 2026 (July 1, 2026)**

Explanation: Union Minister Pralhad Joshi, Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), launched the Green Hydrogen Certification Portal of India (GHCI Portal) in June 2026. This digital platform enables transparent certification, verification, and regulatory compliance for green hydrogen under the GHCI scheme and is scheduled to become fully operational on July 1, 2026, following its final security audit.

स्पष्टीकरण: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने जून 2026 में 'ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया' (GHCI पोर्टल) लॉन्च किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) के तहत पारदर्शी प्रमाणन, सत्यापन और नियामक अनुपालन को सक्षम बनाता है। अंतिम सुरक्षा ऑडिट पूरा होने के बाद यह 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह चालू होने वाला है।

2] To strengthen global oceanic governance and ensure marine ecosystem protection, 15 countries recently adopted the landmark 'Mombasa Declaration'. What is the primary focus of this global declaration?

वैश्विक महासागरीय शासन को मजबूत करने और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, 15 देशों ने हाल ही में ऐतिहासिक 'मोम्बासा घोषणा' (Mombasa Declaration) को अपनाया है। इस वैश्विक घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. Combating Marine Plastic Pollution / समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण का मुकाबला करना

B. Mitigating Coral Bleaching / कोरल ब्लैचिंग (प्रवाल विरंजन) को कम करना

C. Eradicating Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing / अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने को समाप्त करना (Eradicating IUU Fishing)

D. Deep-Sea Mineral Mining Regulation / गहरे समुद्र में खनिज खनन का विनियमन

**✓ Answer: C. Eradicating Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing / अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने को समाप्त करना (Eradicating IUU Fishing)**

Explanation: Adopted by 15 nations across Africa, Asia, Europe, the Caribbean, and the Pacific during the 11th Our Ocean Conference (OOC) in Mombasa, Kenya, the Mombasa Declaration aims to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. It calls for enhanced transparency in regional fisheries by improving public access to vessel logs, corporate ownership, and licensing data to safeguard coastal livelihoods.

स्पष्टीकरण: केन्या के मोम्बासा में आयोजित 11वें 'अवर ओशन कॉन्फ्रेंस' (OOC) के दौरान अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों द्वारा 'मोम्बासा घोषणा' को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने पर रोक लगाना है। यह घोषणा तटीय आजीविका की रक्षा के लिए जहाजों के स्वामित्व, लॉग और लाइसेंसिंग डेटा तक सार्वजनिक पहुंच में सुधार करके पारदर्शिता बढ़ाने का आह्वान करती है।

③ The Central Government successfully facilitated a vital consensus among six beneficiary states for the implementation of the Kishau Multipurpose Dam Project. Along the border of which two states is this major dam project located?

केंद्र सरकार ने किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना (Kishau Multipurpose Dam Project) के कार्यान्वयन के लिए छह लाभार्थी राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण सहमति बनाने में सफलता प्राप्त की है। यह प्रमुख बांध परियोजना किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है?

A. Uttarakhand and Uttar Pradesh / उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश

- B. Himachal Pradesh and Punjab / हिमाचल प्रदेश और पंजाब
- C. Haryana and Himachal Pradesh / हरियाणा और हिमाचल प्रदेश
- D. Uttarakhand and Himachal Pradesh / उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश (Uttarakhand and Himachal Pradesh)

✓ **Answer: D. Uttarakhand and Himachal Pradesh / उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश (Uttarakhand and Himachal Pradesh)**

Explanation: The Kishau Multipurpose Dam Project is located along the Uttarakhand–Himachal Pradesh border on the Tons River, which is the largest tributary of the Yamuna River. The Union Government will bear 90% of the project's water component cost, while the remaining 10% will be shared among six beneficiary states—Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana, and Rajasthan—to secure regional clean drinking water and power.

स्पष्टीकरण: किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी 'टोंस नदी' पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित है। इस परियोजना के जल घटक की लागत का 90% केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 10% लागत छह लाभार्थी राज्यों—हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान द्वारा साझा की जाएगी ताकि क्षेत्र में पीने के पानी और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

4) Who has been appointed by the Central Government as the new Chairperson of the apex statistical body, the National Statistical Commission (NSC), on June 18-19, 2026?

18-19 जून 2026 को केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च सांख्यिकीय निकाय, 'राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग' (National Statistical Commission - NSC) के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A. Dr. Saibal Chattopadhyay / डॉ. सैकत चट्टोपाध्याय (Dr. Saibal Chattopadhyay)
- B. Prof. Shubhabrata Das / प्रो. शुभब्रत दास
- C. Dr. Madhavan Mukund / डॉ. माधवन मुकुंद
- D. Satyendra Bahadur Singh / सत्येंद्र बहादुर सिंह

✓ **Answer: A. Dr. Saibal Chattopadhyay / डॉ. सैकत चट्टोपाध्याय (Dr. Saibal Chattopadhyay)**

Explanation: The Government of India formally appointed Dr. Saibal Chattopadhyay as the new Chairperson of the National Statistical Commission (NSC). The NSC serves as the nodal advisory body for all core statistical activities in the country, responsible for evolving national policies, maintaining data collection standards, and boosting public trust in official national surveys.

स्पष्टीकरण: भारत सरकार ने औपचारिक रूप से डॉ. सैकत चट्टोपाध्याय (Dr. Saibal Chattopadhyay) को राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (NSC) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। NSC देश में सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है, जो राष्ट्रीय नीतियों को विकसित करने, डेटा संग्रह मानकों को बनाए रखने और आधिकारिक राष्ट्रीय सर्वेक्षणों में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है।

5 Branded as "One Nation, One Expo", the mega industrial exhibition 'Bharat Buildcon 2026' was recently inaugurated by union ministries. This international event is directly associated with which core sector?

"वन नेशन, वन एक्सपो" के रूप में ब्रांडेड, मेगा औद्योगिक प्रदर्शनी 'भारत बिल्डकॉन 2026' (Bharat Buildcon 2026) का हाल ही में केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उद्घाटन किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम सीधे तौर पर किस प्रमुख क्षेत्र से जुड़ा हुआ है?

A. Sustainable Agriculture Tech / सतत कृषि तकनीकी

B. Construction and Building Materials / निर्माण और भवन निर्माण सामग्री (Construction and Building Materials)

C. Technical Textiles and Fabrics / तकनीकी वस्त्र और फैब्रिक

D. Pharmaceutical Manufacturing / फार्मास्युटिकल विनिर्माण

✓ **Answer: B. Construction and Building Materials / निर्माण और भवन निर्माण सामग्री (Construction and Building Materials)**

Explanation: Bharat Buildcon 2026 – One Nation, One Expo was grandly inaugurated at the Yashobhoomi Convention Centre in Dwarka, New Delhi. Organized as a flagship platform for the building materials, architecture, and construction sector, the premier international exhibition witnessed operational participation from over 90 global nations and 100 Indian cities showcasing green infrastructure.

स्पष्टीकरण: 'भारत बिल्डकॉन 2026 - वन नेशन, वन एक्सपो' का भव्य उद्घाटन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, द्वारका, नई दिल्ली में किया गया। भवन निर्माण सामग्री, वास्तुकला और

निर्माण क्षेत्र के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 90 से अधिक वैश्विक देशों और 100 भारतीय शहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहाँ हरित बुनियादी ढांचे (Green Infrastructure) का प्रदर्शन किया गया।

यहाँ 19 जून 2026 के लिए बचे हुए 5 महत्वपूर्ण सामयिक घटनाक्रम (Current Affairs) उसी द्विभाषी और विस्तृत प्रारूप में प्रस्तुत हैं:

⑥ The Reserve Bank of India (RBI) on June 18-19, 2026, announced the pilot launch of a specialized institutional platform named 'Udayam Credit Portal'. What is the primary objective of this new financial infrastructure?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 18-19 जून 2026 को 'उदयम क्रेडिट पोर्टल' (Udayam Credit Portal) नामक एक विशेष संस्थागत प्लेटफॉर्म के पायलट लॉन्च की घोषणा की है। इस नए वित्तीय बुनियादी ढांचे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

- A. Instant Retail Housing Loans / तत्काल खुदरा आवास ऋण
- B. Frictionless End-to-End Digital Credit for MSMEs / एमएसएमई (MSMEs) के लिए घर्षण रहित एंड-टू-एंड डिजिटल क्रेडिट (Frictionless Digital Credit for MSMEs)
- C. Cross-Border CBDC Remittances / सीमा पार सीबीडीसी (CBDC) प्रेषण
- D. Rural Agricultural Land Monetization / ग्रामीण कृषि भूमि का मुद्रीकरण

✓ **Answer: B. Frictionless End-to-End Digital Credit for MSMEs / एमएसएमई (MSMEs) के लिए घर्षण रहित एंड-टू-एंड डिजिटल क्रेडिट (Frictionless Digital Credit for MSMEs)**

Explanation: The RBI introduced the 'Udayam Credit Portal' to revolutionize small business lending. Developed by the central bank's innovation hub, the platform aggregates verified data from GSTN, Udyam, and credit bureaus to enable banks to disburse collateral-free, frictionless, and end-to-end digital loans to MSMEs within minutes, drastically reducing documentation delays.

स्पष्टीकरण: आरबीआई (RBI) ने छोटे व्यवसायों के ऋण वितरण में क्रांति लाने के लिए 'उदयम क्रेडिट पोर्टल' पेश किया है। केंद्रीय बैंक के नवाचार हब द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म, जीएसटीएन (GSTN), उदयम और क्रेडिट ब्यूरो से सत्यापित डेटा को एक साथ लाता है ताकि बैंक कुछ ही मिनटों में एमएसएमई को संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) और एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण वितरित कर सकें, जिससे दस्तावेज़ीकरण में होने वाली देरी को काफी हद तक कम किया जा सके।

7] Scientists at the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, in collaboration with global partners, unveiled a groundbreaking bio-computational model on June 19, 2026. This model successfully simulates the neural pathway structures of which specific neurodegenerative condition?

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर 19 जून 2026 को एक अभूतपूर्व बायो-कंप्यूटेशनल मॉडल का अनावरण किया है। यह मॉडल किस विशिष्ट न्यूरोडीजेनेरेटिव स्थिति की तंत्रिका मार्ग संरचनाओं (neural pathway structures) का सफलतापूर्वक अनुकरण करता है?

- A. Multiple Sclerosis / मल्टीपल स्केलेरोसिस
- B. Early-Onset Alzheimer's Disease / शुरुआती दौर की अल्जाइमर बीमारी (Early-Onset Alzheimer's Disease)
- C. Huntington's Chorea / हंटिंगटन कोरिया
- D. Chronic Traumatic Encephalopathy / क्रॉनिक ट्रॉमैटिक एन्सेफैलोपैथी

**Answer: B. Early-Onset Alzheimer's Disease / शुरुआती दौर की अल्जाइमर बीमारी (Early-Onset Alzheimer's Disease)**

Explanation: IISc Bengaluru researchers successfully engineered an AI-driven bio-computational framework that models early-onset Alzheimer's progression. By simulating how amyloid-beta plaques disrupt specific neural pathways, the platform allows pharmaceutical developers to test the efficacy of experimental drugs in a virtual environment before moving to clinical trials.

स्पष्टीकरण: आईआईएससी (IISc) बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक एआई-संचालित बायो-कंप्यूटेशनल फ्रेमवर्क बनाने में सफलता हासिल की है जो शुरुआती दौर के अल्जाइमर के बढ़ने का अनुकरण करता है। अमाइलॉइड-बीटा प्लाक (amyloid-beta plaques) किस तरह विशिष्ट तंत्रिका मार्गों को बाधित करते हैं, इसका अनुकरण करके यह प्लेटफॉर्म फार्मास्युटिकल डेवलपर्स को नैदानिक परीक्षणों (clinical trials) में जाने से पहले एक वर्चुअल वातावरण में प्रयोगात्मक दवाओं की प्रभावकारिता का परीक्षण करने की अनुमति देता है।

8] In an effort to secure strategic international shipping networks, the Indian Navy on June 18-19, 2026, officially commenced 'Exercise Sagar Kavach-II'. In

which volatile maritime zone is this bilateral anti-piracy and escort exercise being executed?

रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नेटवर्क को सुरक्षित करने के प्रयास में, भारतीय नौसेना ने 18-19 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर 'अभ्यास सागर कवच-II' (Exercise Sagar Kavach-II) शुरू किया है। यह द्विपक्षीय समुद्री डकैती विरोधी और एस्कॉर्ट अभ्यास किस अशांत समुद्री क्षेत्र में निष्पादित किया जा रहा है?

- A. South China Sea / दक्षिण चीन सागर
- B. Bab-el-Mandeb Strait & Gulf of Aden / बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी (Bab-el-Mandeb Strait & Gulf of Aden)
- C. Strait of Malacca / मलक्का जलडमरूमध्य
- D. Mozambique Channel / मोजाम्बिक चैनल

**Answer: B. Bab-el-Mandeb Strait & Gulf of Aden / बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य और अदन की खाड़ी (Bab-el-Mandeb Strait & Gulf of Aden)**

Explanation: Responding to persistent asymmetric threats against commercial shipping lines, the Indian Navy deployed frontline guided-missile destroyers for 'Exercise Sagar Kavach-II' in the Gulf of Aden and near the strategic Bab-el-Mandeb Strait. The operations focus on drone deflection, anti-piracy interventions, and providing secure corridors for merchant vessels.

स्पष्टीकरण: वाणिज्यिक शिपिंग लाइनों के खिलाफ लगातार बढ़ते खतरों का जवाब देते हुए, भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी और रणनीतिक बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य के पास 'अभ्यास सागर कवच-II' के लिए अग्रिम पंक्ति के गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को तैनात किया है। यह ऑपरेशन ड्रोन हमलों को विफल करने, समुद्री डकैती विरोधी हस्तक्षेप और व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने पर केंद्रित है।

9) SEBI (Securities and Exchange Board of India) implemented a revised mandate effective June 19, 2026, introducing stricter frameworks for 'Influencers' (Financial Influencers). What major operational restriction has been enforced under this new update?

सेबी (SEBI) ने 19 जून 2026 से प्रभावी एक संशोधित निर्देश लागू किया है, जिसके तहत 'फिनफ्लूएंसर' (वित्तीय प्रभावकार) के लिए कड़े नियम पेश किए गए हैं। इस नए अपडेट के तहत कौन सा बड़ा परिचालन प्रतिबंध लागू किया गया है?

- A. Complete ban on hosting YouTube channels / यूट्यूब चैनल चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध
- B. Mandatory 10-year lock-in period for trading / ट्रेडिंग के लिए अनिवार्य 10 साल की लॉक-इन अवधि
- C. Absolute prohibition on sharing referral fees and profit-sharing models with unregistered brokers / गैर-पंजीकृत ब्रोकरों के साथ रेफरल शुल्क और लाभ-साझाकरण मॉडल साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध (Absolute prohibition on referral sharing with unregistered brokers)

**D. Compulsory daily portfolio disclosure / दैनिक पोर्टफोलियो का अनिवार्य प्रकटीकरण**

✓ Answer: C. Absolute prohibition on sharing referral fees and profit-sharing models with unregistered brokers / गैर-पंजीकृत ब्रोकरों के साथ रेफरल शुल्क और लाभ-साझाकरण मॉडल साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध (Absolute prohibition on referral sharing with unregistered brokers)

Explanation: To safeguard retail investors from biased financial advice, SEBI's updated regulations prohibit regulated stockbrokers and mutual funds from associating, splitting commissions, or paying referral/advertisement fees to unregistered financial influencers. Finfluencers must now obtain formal SEBI registration to offer any commercial investment insights.

स्पष्टीकरण: खुदरा निवेशकों को पक्षपातपूर्ण वित्तीय सलाह से बचाने के लिए, सेबी (SEBI) के अद्यतन नियम विनियमित स्टॉकब्रोकरों और म्यूचुअल फंडों को गैर-पंजीकृत वित्तीय प्रभावकारों (Finfluencers) के साथ जुड़ने, कमीशन बांटने, या रेफरल/विज्ञापन शुल्क का भुगतान करने से प्रतिबंधित करते हैं। व्यावसायिक निवेश अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए फिनफ्लूअंसर्स को अब औपचारिक सेबी पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

**10** The Ministry of Power on June 19, 2026, officially published the 'National Smart Grid Progress Report'. Which state has achieved the highest deployment rate of functional consumer smart prepaid meters in rural sectors across India?

विद्युत मंत्रालय ने 19 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर 'राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड प्रगति रिपोर्ट' (National Smart Grid Progress Report) प्रकाशित की है। किस राज्य ने पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की सबसे अधिक तैनाती दर हासिल की है?



Join Whatsapp

www.freejobalert.com  
**Free Job Alert**  
.com



Download App

- A. Gujarat / गुजरात
- B. Bihar / बिहार (Bihar)
- C. Maharashtra / महाराष्ट्र
- D. Tamil Nadu / तमिलनाडु

✓ **Answer: B. Bihar / बिहार (Bihar)**

Explanation: According to the Ministry of Power's data, Bihar has emerged as the leading state in rolling out advanced smart prepaid meters within rural electricity consumer segments. This mass deployment has substantially reduced Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses for state distribution companies while providing real-time consumption tracking to rural households.

स्पष्टीकरण: विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बिहार ग्रामीण बिजली उपभोक्ता क्षेत्रों में उन्नत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इस बड़े पैमाने पर की गई तैनाती ने राज्य की वितरण कंपनियों के लिए कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) नुकसान को काफी कम कर दिया है, साथ ही ग्रामीण परिवारों को रीयल-टाइम बिजली खपत की निगरानी की सुविधा भी प्रदान की है।